

1337. श्री रामकी साल : क्या प्रथान मंडी यह बराने की कुपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में राष्ट्रीय पंग्रेजन योजना आरम्भ की है;

(स) यदि हों, तो विगत तीन वर्षों के इन्हेरीक तथा 28 फरवरी, 1993 तक के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था और यह लक्ष्य वर्षवार किस सीमा तक हासिल हुआ और इस संबंध में राज्य-वार तथा जिला-वार व्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्स योजना के लिए राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है और 1993-94 के वर्ष के दौरान इस हते क्या प्रावधान किया गया है तथा इसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस होतू क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उसन भाई पटले) : (क) जी, हो ।

(छ) एत तीन वर्षो और 1992-93 के दौरान त्यरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्य-कुम के अंतर्गत राज्यवार और वर्ष्यार लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुपत्र-1 में दिए गए विधरण में दर्शांया गया है। दिशिषए गरि-शिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 28] केन्द्र सरकार के स्तर पर जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। मिनी मिश्चन जिलों में समय लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुपत्र-2 में दर्शाया गया है। दिशिषए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 28]

(ग) गत तीन वर्षों और 1992-93 के दौरान रिसोज को गई राषि के राज्य बहर ज्योरि अनुपन-3 में दर्शीए गए हैं। दिकिए दरिशिष्ट 166, अनुपन संख्या 28 1993-94 के लिए राज्यवार आब्दनु को. अंतिम रूप नहीं दिया गया। ्र(ष) आठती पंचवर्षीय योजना में अमीण क्षेत्रों में स्वच्छ पंगजल की व्यवस्था के लिए जिम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं :---

- --- झेष 21 60 प्रतिवत ग्रामीण जन-संख्या (1991 की गणना के अनुसार) जिसे पंयञ्ज सुविधाएं मुहरैया नहीं कराई गई ह⁴, को पंयञ्ज सुवि-धाएं मुहरैया कराना ।
 - --- मार्च, 1993 तक बकाया 2968 ''बिना जल स्त्रोत'' वाले अधिक समस्ताग्रस्त गांवों मॅं पेयजल की स्विधाए मुहैया कराना ।
- --- 40 सीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से कम पानी वाले आंक्षिक रूप से पंयजल स्विधा प्राप्त गांधों की पूर्ण कवरजे स्निध्चित करना ।
 - अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पंयजल सूविधाएं मुहैया कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दना ।
- --- 1995 तक गिनीकृभि का उन्मूलन करना ।
- --- पेयजल में अन्य जैविक और रासाय-निक संदूषण को दूर करने के लिए समाधान ढढना ।

Performance of Poverty Allegation Programmes

1338. SHRI K. K. BIRLA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the details of the major poverty alleviation programmes under implementation at present with both—physical and financial targets, State-wise;

; (b) what has been their performance during 1991-92 and 1992-93; and what are the agencies through which the allocated 1 amount is distributed for more development;

(c) the details of shortcomings noticed in the' implementation of these program-mes alongwith any evaluation; and

"(d) the steps taken to remove these shortcomings ?

THE 'MINISTER: OF STATE IN" THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHA1

PATEL) :(a) and (b) The major poverty alleviation programmes under implementation in the country are (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP) and (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY). The main objective of IRDP is to enable the identified rural poor families to rise above the poverty line. This objective is sought to be achieved by providing income generation assets to the beneficiaries through Government subsidy and bank loan. As regards JRY this programme aims to generate additional gainful employment for the unemployed/underemployed persons both men and women in the rural areas.

Statements giving details of physical and financial targets and achievements under these programmes during 1991-92 and 1992-93 are given in Annexure-I and II respectively. *[see* Appendix CLXVI, Annexure No. 291.

(c) (d) The Integrated Rural and Development Porgramme is constantly monitored and reviewed in consultation with the State Govts. Other organisations like the Programme Evaluation Organisation (PEO), Reserve Bank of India (RBI), the National Bank for Rural Development (NABARD), Institute for Financial Management & Research (IFMR) and many independent studies have been made ' on this programme. Since, 1986, a process of concurrent evaluation has been initiated by the Ministry involving a large number of reputed research organisations. Three rounds of concurrent evaluation in 1986, 1987 and 1989 have been completed and the fourth round has commenced from September, 1992. Steps ere regularly taken to remove the shortcomings brought out by the evaluation reports.

AB regards JRY, this programme is also being independently evaluated through reputed and independent research organisations. Based on (he evaulation study of JRY made during January to December, 1992, necessary follow up measures are being taken to remove the shortcomings *! and* improve the implementation of the programme.

स्व-राखेगार योजना हरेतु ग्रामीण युवाको क्षा प्रतिकण

1339. श्री राम जॅठमसानी : डा. जिनेन कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करणे कि आठवीं पंचवधींय योजनावधि के दौरान म्त-रोजगार हते ग्रामीण यूवाओं के प्रसिक्षण की योजना के अंतर्गत किल्ने युवाओं को प्रायक्षण दने का विचार है ?

ग्रामोज विकास मंत्रालय (पामोप विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटरेल) : वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में ग्रामीण युवा-स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राईसेम) के अंतर्गत प्रशिक्षित किए जानें वाले प्रस्तावित युवाओं की संख्या कमशः 3 लाख लभा 3.50 लाख है। आठवीं एंच-वर्छीय योजना के शेष वर्षों के लिए अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

Setting up of Indo-Japanese Science Council

1340. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Indo-Japanese Science Council has recently been set up; if so, what are the objectives of the Council;

(b) the names of the personnel of the Council from both the countries; and

(c) the number of meetings of the Council held, so far, and the decisions taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECH-NOLOGY, DEPARTMENT OF ELEC-TRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND MINIS' TER OF STATE IN THE MINISTRY : OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM) :

(a) Sir, such a Council has been formed as an arrangement for facilitating coopera-l live activities between Indian and Japanese scientists.